सीता देवी बनाम राज्य ओए हरियाणा और अन्य (संजय किशन कौल, मुख्य न्यायाधीश)

संजय किशन कौल, मुख्य न्यायाधीश, सूर्यकांत और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, के सामने

सीता देवी-याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य ओए हरियाणा और अन्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपीनं. 2007 का 10006

2 अगस्त 2013

अ. भारत का संविधान, 1950 - कला। 226 - पंजाब सिविल सेवा पुलिस, अध्याय 3, धारा 11, खंड 3.12, खंड 11, भाग / (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है) - पारिवारिक पेंशन - रोजगार वास्तविक और स्थायी होना चाहिए - याचिकाकर्ता की मृत बेटी को अनुबंध के आधार पर भर्ती किया गया - सेवा में जारी रखा गया - दुर्भाग्य से नियमितीकरण के लिए नीति के तहत विचार किए जाने से पहले ही उनका निधन हो गया - निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता अपनी मृत बेटी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी क्योंकि सेवाएं कभी भी नियमित नहीं की गईं।

निर्णय लिया गया कि यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता की मृत बेटी पहले और तीसरे पैरामीटर को पूरा करती थी, विवाद केवल दूसरे पैरामीटर के लिए है जिसके लिए आवश्यक है कि 'रोजगार वास्तविक और स्थायी होना चाहिए'। इस प्रकार, हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से एक प्रश्न पूछा कि याचिकाकर्ता की मृत बेटी की सेवाओं को इन परिस्थितियों में वास्तविक और स्थायी कैसे कहा जा सकता है क्योंकि निर्विवाद रूप से उसे नियमित नहीं किया गया था, हालांकि यह कहा जा सकता है कि वह अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन उत्तरदाताओं की नीति के अनुसार 01.10.2003 को नियमितीकरण के लिए पात्र होगी।

हमारे विचार में, विभिन्न न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए यह मुद्दा अब समाप्त नहीं हुआ है और इस प्रकार, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता अपनी मृत बेटी के

कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता की सेवाओं के बाद से पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। (एसआईसी) को कभी भी नियमित नहीं किया गया। हम तदनुसार संदर्भ का उत्तर देते हैं।

बी. भारत का संविधान, 1950 - कला। 226/227 - अभ्यास और प्रक्रिया - न्यायिक फैसले के लिए - केवल भावनाएं और सहानुभूति आधार नहीं हो सकती - ऐसे पहलुओं पर हमेशा प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकता है।

निर्णय लिया, हालांकि, मामले से अलग होने से पहले, हम यह बताना चाहेंगे कि हालांकि न्यायिक फैसले के लिए केवल भावनाएं और सहानुभूति ही आधार नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे पहलुओं पर हमेशा प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मृतक की बेटी उसी क्षमता में काम करना जारी रखती जिस क्षमता से वह उसके दुर्भाग्यपूर्ण निधन के समय थी, बल्कि वह उत्तरदाताओं की अपनी नीति के अनुसार नियमितीकरण की हकदार होती। 01.10.2003 को. उसे नियमित होने में तीन महीने से थोड़ा ही कम समय बचा था और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि वह अन्यथा हकदार नहीं होती। इस तथ्यात्मक स्थिति के तहत, यह उत्तरदाताओं पर निर्भर करेगा कि क्या वे किसी प्रकार की पेंशन या सहायता के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के इच्छुक हैं जिससे याचिकाकर्ता की पीड़ा में सुधार हो सके।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ता के वकील नवीन दरियाल।

अजय गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

संजय किशन कौल, मुख्य न्यायाधीश (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता की बेटी स्वर्गीय इंदर कौर, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, सुल्तानपुर, ब्लॉक लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र में जेबीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत थीं, जब दुर्भाग्यवश 07.07.2003 को एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता होने के नाते मां ने अपनी मृत्यु की तारीख से ब्याज सहित पारिवारिक पेंशन जारी करने की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर की।

(2) रिट याचिका की सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने दो डिवीजन बेंचों के अलग-अलग फैसलों पर ध्यान दिया, जिन्होंने प्रश्न में भौतिक पहलू के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था। ***उषा रानी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य***[1] में, एक कर्मचारी के आश्रित को पारिवारिक पेंशन का हकदार माना गया था, जिसकी कार्यस्थल पर मृत्यु हो गई थी और वह कार्य-प्रभार के आधार पर काम कर रहा था। दूसरी ओर, 2006 के सीडब्ल्यूपी नंबर 1851 में शांति देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में 07.02.2006 को निर्णय दिया गया, मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि कर्मचारी 'नियमित' होना चाहिए 'पेंशनयोग्य प्रतिष्ठान' पर कर्मचारी। न्यायिक दृष्टिकोण के इस टकराव को देखते हुए इस मामले को दिनांक 30.11.2007 के आदेश के तहत एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह तर्क देना चाहा कि पारिवारिक पेंशन याचिकाकर्ता को वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा अवकाश आदि की स्वीकार्यता की अवधारणा के अनुरूप स्वीकार्य होगी, जो 2005 के सीडब्ल्यूपी संख्या 7520 में समान स्थिति वाले शिक्षकों को दी गई थी। मोहिंदर पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का शीर्षक 17.10.2007 को सुनाया गया। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता की बेटी को भी याचिकाकर्ताओं की तरह ही भर्ती किया गया था, जहां प्रारंभिक नियुक्ति संविदा के आधार पर थी जिसे जारी रखा गया था। याचिकाकर्ताओं ने सेवा बंद होने की आशंका जताते हुए सीडब्ल्यूपी नंबर 9104 का सहारा लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। 1999 का शीर्षक दिनेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य था, जिस पर 13.09.1999 को निर्णय लिया गया था कि राज्य को याचिकाकर्ताओं को नियमित उम्मीदवारों की नियुक्ति होने तक सेवा में बने रहने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता सेवा में बने रहे और इस बीच हरियाणा राज्य ने उन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए 01.10.2003 को एक नीति बनाई जो एक विशेष संख्या में वर्षों से सेवा में थे और तदनुसार याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित किया गया और वे थे। सेवा में, अन्य समान मामलों से संकेत लेते हुए, जहां समान स्थिति वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया था, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सचिव, ***कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी (3) और अन्य***[2] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद वह लाभ दिया।, विशिष्ट तथ्यों के कारण। हम ध्यान दें कि ऐसी पेंशन के लिए पात्र होने के लिए योग्यता की शर्तों के बारे में कोई विवाद नहीं है जो पंजाब सिविल सेवा नियमों के अध्याय 3 खंड II खंड 3.12 (हरियाणा राज्य पर लागू) खंड 11 भाग I में शामिल हैं। प्रासंगिक खंड निम्नानुसार पढ़ता है:-

[1] 2005(1) SCT410
[2] (2006) 4 SCC

"3.12 किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा तब तक पेंशन के लिए योग्य नहीं होती जब तक कि वह निम्नलिखित तीन शर्तों के अनुरूप न हो:- पहली - सेवा उसे सरकार के अधीन होनी चाहिए।

दूसरा - रोज़गार ठोस और स्थायी होना चाहिए। तीसरा - सेवा का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

इन तीन स्थितियों को निम्नलिखित नियमों में पूरी तरह से समझाया गया है।

नोट.- यह प्रश्न कि क्या किसी विशेष कार्यालय या विभाग में सेवा पेंशन के लिए योग्य है या नहीं, उन नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है जो उस समय लागू थे (उन्होंने कहा कि ऐसी सेवा प्रदान की गई थी और बाद में सेवा को गैर-अर्हता घोषित करने के आदेश जारी किए गए थे, यह लागू नहीं होता) पूर्वव्यापी प्रभाव।"

(5) इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की मृत बेटी पहले और तीसरे मापदंडों को पूरा करती है। 'यह विवाद केवल दूसरा पैरामीटर है जिसके लिए आवश्यक है कि 'रोजगार वास्तविक और स्थायी होना चाहिए'। इस प्रकार, हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से एक प्रश्न पूछा कि याचिकाकर्ता की मृत बेटी की सेवाएं कैसे दी जा सकती हैं इन परिस्थितियों में इसे वास्तविक और स्थायी कहा जाता है क्योंकि निर्विवाद रूप से उसे नियमित नहीं किया गया है, हालांकि यह कहा जा सकता है कि वह अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन उत्तरदाताओं की नीति के अनुसार 01.10.2003 को नियमितीकरण के लिए पात्र होती।

(6) उत्तरदाताओं के लिए अर्जित वकील ने ***हरियाणा राज्य और अन्य बनाम शकुंतला देवी***[3] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी आपत्ति जताई है, जहां पैरा 31 में यह समझाया गया है कि मूल का क्या मतलब है और स्थायी रोजगार। ऐसा तभी होता है जब कोई कर्मचारी पेंशन योग्य सेवा प्रदान करता है, क्या वह पेंशन का हकदार होगा, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। उक्त निर्णय के पैरा 31 से 33 में इसे अनुचित माना गया:-

"31. नियमों का खंड 3.17 बिना किसी अनिश्चित अवधि के स्पष्ट करता है कि वास्तविक और स्थायी रोजगार का क्या मतलब है। वकील का तर्क (केवल एक व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो चुका है, लागू होता है) सही नहीं है क्योंकि एक स्थायी स्थायी रोजगार का होना सही नहीं है सेवानिवृत्ति की तारीख पर पोस्ट के बाद "उसकी अस्थायी या राज्य सरकार के तहत स्थानापन्न सेवा" शब्द आते हैं। इसलिए, सेवा में पुष्टि, चाहे सेवानिवृत्ति से पहले हो या मृत्यु से पहले, पेंशन अनुदान के

[3] (200 8) 15 SCC 3 8

लिए पात्र बनने के लिए अनिवार्य शर्त मानी जानी चाहिए। .जब कोई कर्मचारी पेंशन योग्य सेवा में सेवा देगा तभी वह पेंशन का हकदार होगा।

(32) केवल सेवा के अनुबंध और/या उसे नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के कारण ही कोई व्यक्ति पूर्ण सरकारी कर्मचारी बन सकता है। जब सेवा के नियम और शर्तें किसी क़ानून या वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह रोजगार के अनुबंध पर लागू होगा, लेकिन फिर उक्त उद्देश्य के लिए, संबंधित कर्मचारी को यह दिखाना होगा कि नियुक्ति नियमित प्रकृति की थी और एक पद पर थी। जो एक कैडर पोस्ट है। सरकारी कर्मचारी तभी दर्जा प्राप्त करता है जब वह किसी क़ानून के कारण इसका हकदार हो जाता है या उसके नियोक्ता द्वारा उसे इसका हकदार घोषित कर दिया जाता है।

(33) जब एक नियमितीकरण योजना बनाई गई थी (यह मानते हुए कि ऐसी योजना वैध और संवैधानिक है) तो कर्मचारी को नियमित किया जाना चाहिए। कम से कम उसे सेवा में नियमित होने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। ”

(7) ***उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम सुरजी देवी*** [4] मामले के फैसले का भी संदर्भ दिया गया है, जहां वर्तमान मामले की तरह ही नियम प्रश्न में था। मृतक को कार्य-प्रभार के आधार पर नियुक्त किया गया था और उसकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया था। यह माना गया कि वैधानिक प्रावधान परिवार के सदस्यों के पक्ष में पारिवारिक पेंशन देने से रोकते हैं क्योंकि बर्खास्त कर्मचारी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नहीं था। आगे यह देखा गया कि केवल भावनाओं और सहानुभूति को कानून में स्वीकार्य से अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है और जिस अवधि के दौरान एक कर्मचारी ने वर्क-चार्ज कर्मचारी के रूप में काम किया था, उस पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब उसकी सेवाएं नियमित हो जाएं और वह स्थायी हो जाता है अन्यथा नहीं।

(8) हमारे विचार में, विभिन्न न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है और इस प्रकार, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता अपनी मृत बेटी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में सेवाओं के बाद से पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। याचिकाकर्ता (एसआईसी) को कभी भी नियमित नहीं किया गया। हम तदनुसार संदर्भ का उत्तर देते हैं।

[4] (2008)2 SCC 31

(9) उपरोक्त स्थिति और संदर्भ के उत्तर को देखते हुए, याचिका में वास्तव में कुछ भी नहीं बचा है, जो खारिज करने योग्य है।

(10) हालांकि, मामले से अलग होने से पहले, हम यह बताना चाहेंगे कि हालांकि न्यायिक फैसले के लिए केवल भावनाएं और सहानुभूति ही आधार नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे पहलुओं पर हमेशा प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मृतक की बेटी उसी क्षमता में काम करना जारी रखती जिस क्षमता से वह उसके दुर्भाग्यपूर्ण निधन के समय थी, बल्कि वह उत्तरदाताओं की अपनी नीति के अनुसार नियमितीकरण की हकदार होती। 01.10.2003 को उसे नियमित होने में तीन महीने से थोड़ा ही कम समय बचा था और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि वह अन्यथा हकदार नहीं होती। इस तथ्यात्मक स्थिति के तहत, यह उत्तरदाताओं पर निर्भर करेगा कि क्या वे किसी प्रकार की पेंशन या सहायता के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के इच्छुक हैं जो याचिकाकर्ता की पीड़ा को कम कर सके।

(11) याचिका उपरोक्त शर्तों के अनुसार खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा